



देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया

मीराबाई चानू का 12 साल का इंतजार खत्म,
एशियन गेम्स में जीता ऐतिहासिक रजत

भारतार्थ खबर
Bhaaraataarth.com
वांशिंगटन, 23 सितंबर 2026।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रमुख मीडिया संस्थानों के बीच व्हाइट हाउस में प्रवेश को लेकर विवाद अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों पर व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इन तीनों मीडिया संस्थानों ने संघीय अदालत का रुख किया है। इसी बीच प्रमुख अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्कों की सझा राष्ट्रपति कवरेज व्यवस्था यानी TV Press Pool भी प्रभावित हुई है और व्हाइट हाउस ने अपनी 24 घंटे चलने वाली ऑनलाइन वीडियो सेवा 'TRUMP TV: The Essentials Station' शुरू कर दी है। ट्रंप ने 18 सितंबर को CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस कवरेज से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। ट्रंप ने इन संस्थानों की रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताते हुए उन्हें गलत या 'फेक न्यूज़' प्रकाशित करने का आरोप लगाया। इसके बाद संघीय पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर

में प्रवेश से रोका गया और उनके प्रेस पास वापस लिए गए। इसके विरोध में CNN, MS NOW

व्हाइट हाउस में प्रवेश का स्वतः अधिकार नहीं देता। इस मामले में अदालत की सुनवाई आगे जारी है।



और Politico ने 21 सितंबर को सघीय अदालत में संयुक्त मुकदमा दायर किया। मीडिया संस्थाओं का कहना है कि प्रतिबंध प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े प्रथम संशोधन के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्होंने अपने व्हाइट हाउस एक्सेस को बहाल करने की मांग की है। व्हाइट हाउस की ओर से प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा गया है कि प्रथम संशोधन प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन किसी विशेष मीडिया संस्थान को

यहा है TV Press Pool? अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की टेलीविजन कवरेज के लिए TV Press Pool एक साझा व्यवस्था है। इसके तहत प्रमुख नेटवर्क—बारी—बारी से राष्ट्रपति के कार्यक्रमों यात्राओं और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और फुटेज को दूसरे मीडिया संस्थानों के साथ साझा करते हैं। ABC CBS CNN Fox News और NBC इस व्यवस्था में प्रमुख नेटवर्कों में शामिल हैं। इसका उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना है कि सीमित स्थान या सुरक्षा व्यवस्था के कारण सभी मीडिया संस्थानों के कैमरा दल किसी कार्यक्रम में मौजूद न रह सकें, तब भी राष्ट्रपति की सार्वजनिक गतिविधियों की वीडियो कवरेज व्यापक मीडिया तक पहुंच सके। CNN पर प्रतिबंध के बाद साझा कवरेज प्रभावित CNN की निर्धारित पूल क्यूटी के दौरान उसे व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश नहीं मिलने के बाद अन्य प्रमुख नेटवर्कों ने उसकी जगह कवरेज संभालने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति के कुछ कार्यक्रमों की परंपरिक साझा टीवी पूल कवरेज रोक दी गई। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी टीवी चैनलों ने ट्रंप की खबरों का पूर्ण रूप से प्रसारण बंद कर दिया है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग बॉक्स अन्य माध्यमों से समाचार कवरेज जारी है। व्हाइट हाउस ने शुरू किया TRUMP TV मीडिया विवाद के बीच व्हाइट हाउस ने 21 सितंबर को TRUMP TV: The Essentials Station नाम से 24 घंटे की डिजिटल वीडियो स्ट्रीम शुरू की। व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसकी घोषणा की गई है। यह सेवा प्रशासन के भाषणों

घोषणाओं, प्रमुख कार्यक्रमों और चयनित वीडियो सामग्री को सीधे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस डिजिटल स्ट्रीम पर ट्रंप के पुराने भाषणों और प्रशासन से जुड़े वीडियो भी प्रसारित किए जा रहे हैं। इसे पारंपरिक टेलीविजन नेटवर्क पर निर्भर हुआ बिना व्हाइट हाउस की ओर से अनुमति के प्रसारित वीडियो सामग्री सीधे दर्शकों तक पहुँचाने के माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। विवाद का अगला पड़ाव अदालत [CNN] MS NOW और POLITICO की संयुक्त याचिका के बाद विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा अब न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ गया है। मीडिया संस्थानों ने प्रतिबंध को चुनौती देते हुए प्रथम संशोधन के तहत प्रेस स्वतंत्रता के अधिकारों का हवाला दिया है जबकि ट्रंप प्रशासन ने मीडिया संस्थानों की व्हाइट हाउस तक पहुँच पर अपने अधिकारों का बचाव किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी राष्ट्रपति और मीडिया के संबंध, संसदीय संस्थानों में पत्रकारों की पहुँच तथा स्वतंत्र और साझा प्रेस कवरेज की व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है। फिनहल आगे की हिंसा अदालत की सुनवाई और व्हाइट हाउस की मीडिया नीति से जुड़े निर्णयों पर निर्भर करेंगे।

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नागोया, 23 सितंबर 2026 । भारत
की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने
एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के
49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक
जीतकर अपने लंबे इंतजार को समाप्त



कर दिया। नागोया में बुधवार को हुए मुकाबले में चानू ने कुल 198 किलोग्राम भार उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। यह एशियन गेम्स में उनका पहला पदक है। चानू ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ भार उठाया। उनके कुल 198 किलोग्राम के प्रदर्शन ने उन्हें रजत पदक दिलाया।

इंडोनेशिया की लुलुक डायना त्रिविजायाना ने 191 किलोग्राम के कुल्लुभार के साथ कांस्य पदक हासिल किया। 12 साल के इंटरजार के बाद, मिता एशियन गेम्स पदक मीराबाइइचानू ने वर्ष 2014 में एशियन गेम्स में पदार्पण किया था। इसके बाद चोट

किया। 49 किग्रा वर्ग में मजबूत प्रदर्शन प्रतियोगिता में चानू ने 87 किलोग्राम के स्नैच के साथ शुरुआत की। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 111 किलोग्राम का भार उठाया। दोनों वर्गों के कुल प्रदर्शन के आधार पर उनका स्कोर 198 किलोग्राम रहा। उत्तर कोरिया की री सोंग गुम ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कुल 218 किलोग्राम भार उठाया, जिसमें 94 किलोग्राम स्नैच और 121 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क शामिल था। री वेंग प्रदर्शन के साथ इस स्पर्धा में नए रिकॉर्ड भी बने। भारतीय भारोत्तोलकों के लिए भी अहम उपलब्धि मिराबाई चानू का रजत पदक केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं है। इससे एशियन गेम्स में भारोत्तोलन भारोत्तोलन का लंबे समय से चल आ रहा पदक का इंतजार भी समाप्त हुआ। भारत ने इससे पहले एशियन गेम्स में भारोत्तोलन का पदक 1998 में जीता था, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने बैंकॉक एशियन गेम्स में रजत पदक हासिल किया था। इस लिहाज से चानू का नागोया रजत भारतीय भारोत्तोलन के लिए 28 साल बाद आया पदक है।

SIR पर घमासान: दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों
पर आयोग ने कहा सभी फैसले सर्वसम्मति से

भारतार्थ खबर
Bhaaraataarth.com
नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण
यानी स्पेशल डेटेंसिव रिवीजन (SIR)
को लेकर चुनाव आयोग के भीतर
कथित मतभेदों की एक रिपोर्ट के बाद
राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संघू
और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों
में कम से कम 14 मौकों पर आयोग
के कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर
लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट के
अनुसार, इन आपत्तियों में मतदाता
नाम जोड़ने-हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव
और मतदाता डेटाबेस के संचालन
जैसे मुद्दे शामिल थे। हालांकि, चुनाव
आयोग ने इन रिपोर्टों से अलग तथ्यीर
पेश की है। आयोग के सूत्रों के अनुसार,
‘सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों
तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से
लिए गए हैं। आयोग ने यह भी कहा
कि किसी मुद्दे पर आयुक्तों द्वारा सवाल
उठाना, सुझाव देना या आपत्ति दर्ज
करना आंतरिक विचार-विमर्श की
सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे

अंतिम निर्णय पर औपचारिक असहमति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 14 आपत्तियों का दावा, कई अहम मुद्दे चर्चा में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संधू और जोशी ने कथित तौर पर 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ



फैसलों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें चार आपत्तियाँ एक ही दिन दर्ज की गई थीं। रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रमुख मुद्दा नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 में बदलाव का था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईप् से संबंधित एक नया प्रश्न ऑनलाइन फॉर्म में जोड़ा गया था और संघ ने इसे कथित रूप से 'अनधिकृत और अवैध' बताते हुए हटाने का बल काही थी। दूसरा मुद्दा मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस

और उसके संचालन से संबंधित बताया गया है। रिपोर्ट में दोनों आयुक्तों द्वारा मतदाता डेटाबेस के 'क्रमिक केंद्रीकरण' को लेकर चिंता जताए जाने का उल्लेख है। इसीमें यह सवाल भी उठाना गला है कि स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने वाले वैधानिक अधिकारियों की डिजिटल सिस्टम तक पहुंच किस सीमा तक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल और गोवा से जुड़े मामलों का भी उल्लेख रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में ५८ के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने और उसके बाद अपील की प्रक्रिया को लेकर भी सवालों का उल्लेख है। चुनाव आयोग

ने हाल में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पश्चिम बंगाल में ५८ के दौरान हटाए गए करीब 27.16 लाख मतदाताओं में से 22 लाख से अधिक ने पुनर्बहाली को लिए अपील की है। कुल मिलाकर 38.31 लाख अपीलों दायर होने की जानकारी आयोग ने अदालत को दी थी। इसी तरह, रिपोर्ट में गोवा में सॉफ्टवेयर से जुड़ी एक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण कथित तौर पर 9९ ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो सके।

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026
दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में
मंगलवार देर रात मैक्स हॉस्पिटल
रोड के पास अतिक्रमण हटाने और



सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी कार्रवाई के दौरान मदीना मस्जिद के एक हिस्से तथा आसपास की कुछ संरचनाओं को हटाया गया। कारवां के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध और राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। नागरिक अधिकारियों के अनुसार, अभियान सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सड़क के लिए आवश्यक जगह यानी

कराने और सार्वजनिक भूमि पर मौजूद कथित अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इसी सड़क पर इससे पहले भी चौड़ीकरण से संबंधित कार्रवाई की जा चुकी है। रिपोर्टों के मुताबिक,

चौड़ीकरण के लिए पहले भी कुछ संरचनाएं हटाई गई थीं। मदीना मस्जिद के हिस्से को लेकर विवाद कार्रवाई में मदीना मस्जिद का हिस्सा भी प्रभावित हुआ। प्रशासन की ओर से संबंधित संरचनाओं को साइकल चौड़ीकरण और कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जोड़ा गया है। वहीं, मस्जिद प्रबंधन ने कार्रवाई की प्रक्रिया और नोटिस को लेकर सवाल उठाए हैं। मस्जिद अध्यक्ष मोविन खान के अनुसार, प्रबंधन को नारा निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए थे और बाद में मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल तक भी पहुंचा। उनका दावा है कि निर्माण के अलग-अलग हिस्सों की वैधता को लेकर वहां हिस्साई हुई थी। मस्जिद प्रबंधन ने यह भी दावा किया कि कुछ ऊपरी मंजिलों के निर्माण को वर्ष 2001 से पुराना बताते हुए संबंधित दस्तावेज और साइट प्लान प्रस्तुत किए गए थे। इन दावों की अंतिम जानकारी स्थिति संबंधित न्यायिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगी। AIMIM नेता शोएब जमाई मौके पर पहुंचते कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई मौके पर पहुंचे।

उन्होंने दर रात की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताई और इसे असंवैधानिक बताया। यह उनका राजनीतिक आरोप है। जमाई ने दावा किया कि उन्होंने रात करीब 11 रु० 30 बजे घटना की जानकारी मली, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्थानीय टीम को मौके पर भेजा और स्वयं भी शालीमार बाग पहुँचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद के भीतर मौजूद दस्तावेजों और धार्मिक सामग्रियों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इन आरोपों पर उपलब्ध रिपोर्टों में नागरिक प्रशासन की ओर से विस्तृत बिदुवा प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस लिए इन्हें संबंधित पक्ष के दावे के रूप में ही देखना जाना चाहिए। नोटिस और कार्रवाई प्रक्रिया पर अलग-अलग दावों में मदीना मस्जिद के अध्यक्ष मोविन खान ने कहा कि नगर निगम की ओर से उन्हें कई नोटिस मिले थे और उनके अनुसार, दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियाँ प्राप्त करने और जवाब तैयार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई तथा मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल तक पहुँचा। दूसरी ओर कुछ रिपोर्टों में प्रशासनिक कार्रवाई को पूर्व में जारी नोटिस और सूचनाओं के पर्याप्त न होना बताया गया है।

चौड़ीकरण परियोजना से जोड़ा गया है। एक अन्य रिपोर्ट में कार्रवाई के न्यायिक आदेश के बाद किया गया अभियान बताया गया है। इसलिए इस मामले में नोटिस की तारीख न्यायिक आदेश की सटीक शर्तों और संबंधित भूमि एवं निर्माण दस्तावेज महत्वपूर्ण होंगे। उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर इन सभी पहलुओं पर एक समान विवरण विधान सभा अत्र है। रेखा गुलाब के विधानसभा क्षेत्र में कार्रवाई शान्ति बाग दिल्ली क्षेत्र की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र है। AIMIM नेता शोएब जमाई ने इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री और प्रशासन से कार्रवाई के समय तथा तरीके को लेकर सवाल पूछे। जमाई ने यह भी कहा कि उनकी आपत्ति केवल एक समुदाय से संबंधित मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्रवाई की प्रक्रिया और देर रात किए गए अभियान को लेकर है। यह बयान राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। प्रशासन के अनुसार सड़क चौड़ीकरण मुख्य वजह उपलब्ध रिपोर्टों में नागरिक अधिकारियों का पक्ष स्पष्ट रूप से सड़क चौड़ीकरण और कठिना

भारत की आर्थिक रफ्तार पर S-P का भरोसा, FY27 में 7: विकास का अनुमान

भारतार्थ खबर
Bhaaraataarth.com

संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026।

भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर वैश्विक रेटिंग एजेंसी S-P Global Rating ने अपना आकलन सुधारा है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का अनुमान पहले के 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। S-P के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपेक्षा से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन ने इस संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक गतिविधि और घरेलू मांग बनी ताकत S-P Global Rating के ताजा एशिया-प्रशांत आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, भारत की वृद्धि को मजबूत औद्योगिक गतिविधि, घरेलू खपत, वस्तु निर्यात और सरकारी निवेश से सहारा मिला है। इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण एजेंसी ने अपने पिछले अनुमान में 0.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि की है।

भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत मजबूत आधार के साथ की है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही



में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही। इस दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के साथ निवेश तथा घरेलू खपत ने भी आर्थिक गतिविधियों को समर्थन दिया। दूसरी छमाही में रपतार पर रह सकती है नजर S-P का अनुमान केवल सकारात्मक पहलुओं तक सीमित नहीं है। एजेंसी ने संकेत दिया है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास

की गति कुछ नरम पड़ सकती है। इसके पीछे वस्तु एवं सेवा कर (GST) के युक्तिकरण तथा आयकर कटौती से मिलने वाले शुरुआती प्रोत्साहन का

क रफ्तार पर नुमान

27 की विकास दर नुमान जताया

FY27 7% GROWTH

INVEST GROW DEVELOP A STRONGER INDIA

DP

स की नई उड़ान

भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय खबर

क्या भी देखें जानें

www.bharatnews.com

प्रभाव धीरे-धीरे कम होना एक कारण माना गया है। मौसम से जुड़े जोखिमों पर भी निगरानी जरूरी बताई गई है। S-P के अनुसार, इस मामले में सत्र में 9 सितंबर तक संघयी बारिश सामान्य से 15 प्रतिशत कम थी। ऐसे में कृषि उत्पादन और खाद्य महंगाई आने वाले महीनों में और खराब परिदृश्य के महत्वपूर्ण कारक रह सकते हैं। महंगाई और

मौद्रिक नीति भी अहम विकास दर के साथ महंगाई और ब्याज दरों का रुख भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। S-P Global Ratings ने भारत के लिए 2026 में औसत उपभोक्ता महंगाई दर 5.1 प्रतिशत और 2027 में 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया है। ब्याज दरों को लेकर बाजार में भी सतर्कता बनी हुई है। हालिया आर्थिक आकलनों में तेल की कीमतों वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू तत्त्वता जैसे कारकों को मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि किसी भी संभावित नीतिगत फैसले को RBI का जोषित निर्णय नहीं माना जा सकता, जब तक केंद्रीय बैंक स्वयं इसकी घोषणा न करे। वैश्विक परिस्थितियां बनी चुनौती भारत की विकास संभावनाओं के साथ वैश्विक आर्थिक वातावरण भी जुड़ा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव, पूंजी प्रवाह और वैश्विक व्यापार की स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष असर डाल सकती है। S&P Global Ratings ने अपने व्यापक एशिया-प्रांशत आकलन में भी ऊर्जा कीमतों, महंगाई और मौद्रिक नीति से जुड़े जोखिमों को महत्वपूर्ण माना है। विकास के साथ गुणवत्ता पर भी नजर जरूरी 7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक महत्वपूर्ण संकेत है, लेकिन आर्थिक विकास का मूल्यका केवल GDP की एक दर से नहीं किया जा सकता। रोजगार सृजन ग्रामीण मांग, कृषि आय, निजी निवेश महंगाई और आम परिवारों की क्रय शक्ति जैसे पहलू भी विकास की व्यापक तस्वीर तय करेंगे। फिलहाल S-P का संशोधित अनुमान भारत की आर्थिक गतिविधियों में बनी मजबूती को रेखांकित करता है। आम वाले महीनों के औद्योगिक उत्पादन, उपभोग, निर्यात, निवेश, महंगाई और मानसून से जुड़े आंकड़े यह स्पष्ट करेंगे कि 7 प्रतिशत के विकास अनुमान के अनुरूप आर्थिक रफ्तार किस हद तक बनी रहती

वैश्विक 'चार एफ' संकट पर जयशंकर का जोर,
आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता की वकालत

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
न्यूयॉर्क, 23 सितंबर 2026 | संयुक्त
राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सत्र के



आपूर्ति शुंखलाओं को अधिक मजबूत, भरोसंद और विविध बनाना महत्वपूर्ण है। जलशुद्धि के बहुउद्देशीय सहयोगों और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया। भारत का रुख रहा है कि बदलती आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक प्रभावी और वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाना

चाहिए। खाद्य, ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति पर दबाव वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और परिवहन मार्गों में व्यवधान का असर खाद्य तथा उर्वरक बाजारों



संयुक्त राष्ट्र में जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग का दिवा संदेश

खाद्य, ऊर्जा, ईंधन और वित्तिय विषय पर और

2014 World Food Summit

खाद्य सुरक्षा, ईंधन सुरक्षा, उर्वरक सुरक्षा, वित्तिय सुरक्षा

पर भी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंत्रों पर इस बात की रेषांकित किया गया है कि ईंधन और उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी कृषि उत्पादन खाद्य कीमतों और विकासशील देशों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकती है। ऐसे परिदृश्य में किसी एक देश, क्षेत्र या आपूर्ति मार्ग पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम बढ़ा सकती है। जयशंकर के वक्तव्य का प्रमख

पक्ष भी यही रहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऐसे आपूर्ति तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जो किसी एक श्रोत या मार्ग में व्यवधान आने पर भी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रख सकें। आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता पर जोर भारत की ओर से लंबे समय से महत्वपूर्ण वस्तुओं और ऊर्जा संसाधनों के लिए श्रोतों में विविधता लाने पर जोर दिया जाता रहा है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक बाजारों में आने वाला व्यवधान दूसरे क्षेत्रों की कीमतों और उत्पादन लागत को भी प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से जुड़े हालिया विमर्श में भी ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा को आपस में जुड़ी चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया गया है। इन व्यवधानों का असर व्यापार, परिहहन, मुद्रास्फीति और विकासशील देशों की वित्तीय स्थिति तक पहुंच सकता है।

सम्पादकीय

SIR विवाद:मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता सबसे जरूरी

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

लोकतंत्र में मतदाता सूची केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं होती। यही वह आधार है जिसके माध्यम से नागरिक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करता है। इसलिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की प्रत्येक प्रक्रिया जितनी निष्पक्ष होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का भरोसा उत्तना ही मजबूत होगा। इसी संदर्भ में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर सामने आया ताजा विवाद गंभीर सार्वजनिक विमर्श की मांग करता है। 23 सितंबर को मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संघु और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में मतदाता सूची, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने और चुनौती डेटाबेस से जुड़े कुछ फ़ैसलों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट में इन आपत्तियों को आंतरिक दस्तावेजों के आधार पर बताया गया है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने इन रिपोर्टों के दाव स्पष्ट किया कि आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से हुए हैं। आयोग के अनुसार अलग-अलग विचार या टिप्पणियां किसी संस्थागत विचार–विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं और अंतिम निर्णय पूर्ण आयोग की सहमति से लिए गए। यहीं से असली प्रश्न शुरू होता है क्या SIR पर राजनीतिक विवाद से आगे बढ़कर उसकी पूरी प्रक्रिया को जनता के सामने पर्याप्त रूप से पारदर्शी बनाया जा सकता है? SIR की जरूरत और चुनौती

मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और गलतियों को सुधारना शामिल होता है। SIR का उद्देश्य भी मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। मई 2026 में सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार SIR के तीसरे चरण में 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया तथा 36.73 करोड़ मतदाताओं तक बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से पहुंचने की योजना बनाई गई। इतने बड़े पैमाने की प्रक्रिया में प्रशासनिक चुनौती स्वाभाविक है। लेकिन जितना बड़ा अभियान होगा, उतनी ही अधिक आवश्यकता स्पष्ट नियमों, सार्वजनिक सूचना और शिकायत निवारण की होगी। आपत्तियां और आयोग का जवाब ताजा विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रिपोर्ट में दो निर्वाचन आयुक्तों की आपत्तियों का उल्लेख किया गया है, जबकि आयोग का कहना है कि अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से हुए। इन दोनों बातों को अलग–अलग समझना जरूरी है। किसी संस्था के भीतर किसी प्रस्ताव पर सवाल या टिप्पणी उठाना और अंतिम निर्णय पर औपचारिक असहमति होना एक ही बात नहीं है। इसी तरह आयोग का सर्वसम्मति का दावा यह स्पष्ट करता है कि उसके अनुसार अंतिम संस्थागत निर्णयों में तीनों आयुक्तों की स्वीकृति थी। इसलिए सार्वजनिक बहस का केंद्र केवल यह नहीं होना चाहिए कि किसने किस पर आपत्ति की, बल्कि यह भी होना चाहिए कि आपत्तियों का निपटारा किस प्रक्रिया से हुआ, अंतिम निर्णय किस आधार पर लिया गया और उससे संबंधित रिकॉर्ड किस सीमा तक सार्वजनिक किए जा सकते हैं। मतदाता के लिए प्रक्रिया कितनी स्पष्ट है?

मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजनीतिक दल नहीं, बल्कि आम मतदाता है। किसी नागरिक का नाम सूची में है या नहीं, उसे अपने नाम की स्थिति कैसे पता चलेगी, यदि नाम हट गया है तो उसे कारण कैसे बताया जाएगा और वह पुनः नाम जुड़वाने के लिए कहां तथा किस समय सीमा में आवेदन कर सकता है इन सवालों के जवाब सरल भाषा में उपलब्ध होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध सारांश के अनुसार SIR के संदर्भ में पहचान, नोटिस, जांच और सुनवाई जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को महत्वपूर्ण माना गया है। अदालत ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट सूची से किसी नाम का बाहर रह जाना अंतिम स्थिति नहीं है और प्रक्रिया में जांच तथा सुनवाई के चरण मौजूद हैं। यही सिद्धांत व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है तो उसे स्पष्ट कारण, आपत्ति दर्ज करने का अवसर और समयबद्ध अपील व्यवस्था मिलनी चाहिए। तकनीक के साथ मानवीय निगरानी भी जरूरी

आज मतदाता सूची का बड़ा हिस्सा डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर है। इससे रिकॉर्ड संभालना और बड़े पैमाने पर डेटा का श्रवण आसान हुआ है। लेकिन तकनीकी खराब अभिन सत्य नहीं हो सकती। डेटाबेस में नाम, पता, उम्र या पारिवारिक संबंध से संबंधित विसंगति सामने आ सकती है। ऐसे मामलों में डिजिटल संकेत को अंतिम निर्णय का आधार बनाने के बजाय स्थानीय स्तर पर अधिकृत अधिकारी द्वारा दस्तावेजों और नागरिक की बात की जांच आवश्यक है। हालिया रिपोर्ट में भी चुनावी डेटाबेस तक पहुंच और आईटी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाने का उल्लेख है।

भारत की 7: विकास दर:आंकड़े मजबूत, लेकिन रोजगार और महंगाई की कसौटी जरूरी

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी ताजा खबरेंउत्साह बढ़ाने वाली हैं। अंतरराष्ट्रीय रेंटिंग एजेंसी S-P Global ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले उसका अनुमान 6.6 प्रतिशत था। इसी दिन एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भी भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया है। ADB ने इसके पीछे निवेश मांग की मजबूती और सेवा निर्यात की बेहतर स्थिति को प्रमुख आधार बताया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी। S-P के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों घरेलू खपत, वस्तु निर्यात और सरकारी निवेश ने इस प्रदर्शन को सहारा दिया। सितंबर के शुरूआती कारोबारी संकेत भी अर्थव्यवस्था में गति लौटने की ओर इशारा करते हैं। HSBC के प्रवेश कंपोजिट PMI के अनुसार सितंबर में निजी क्षेत्र की गतिविधियों का सूचकांक 56.5 रहा, जो अगस्त के 54.3 से बेहतर है। विनिर्माण PMI 55.7 और सेवा PMI 55.8

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने एक बार फिर भारत की ऊर्जा सुरक्षा की परीक्षा शुरू कर दी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव और महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों में व्यवधान के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि देश अपनी घरेलू जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ताजा आकलन के अनुसार, भारतीय कच्चे तेल की टोकरी की कीमत 21 सितंबर को करीब 117.4 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई, जबकि वित्त वर्ष 2025–26 में इसका औसत पेट्रोल–डीजल कीमतों पर बरकत था। इस तेज अंतर ने देश की तेल विपणन कंपनियों की लागत और खुदरा ईंधन कीमतों के बीच दबाव बढ़ा दिया है। रेंटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, घरेलू पेट्रोल–डीजल कीमतों में बदलाव नहीं होने की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 8 रुपये और डीजल पर करीब 9 रुपये प्रति लीटर की नकारात्मक मार्केटिंग मार्जिन का सामना करना पड़ रहा है। ICRA ने इन कंपनियों के लिए प्रतिदिन लगभग 530 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान जताया है। घरेलू एलपीजी पर सितंबर में प्रति लिसेंटर करीब 300 रुपये की अंडर–रिकवरी का भी आकलन किया गया है। यह आंकड़ा केवल तेल कंपनियों की बेलेस शीट का विषय नहीं है। इसके पीछे परिवहन लागत, माल ढुलाई, कृषि लागत, उद्योगों की उत्पादन लागत और अंततः आम परिवार के

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI अब केवल तकनीकी प्रयोगशालाओं और बड़ी कंपनियों का विषय नहीं रह गया है। यह अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मीडिया, लोकतंत्र और मानव निर्णय क्षमता तक पहुंच चुका है। जिस गति से AI की क्षमताएं बढ़ रही हैं, उसी गति से उसके इस्तेमाल को लेकर नैतिक, कानूनी और सामाजिक प्रश्न भी सामने आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने AI के लिए अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था, सुरक्षा मानकों और स्वतंत्र निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि AI विकसित करने वाले देशों को सुरक्षा जोखिमों की जानकारी साझा करनी चाहिए, परीक्षण और मूल्यांकन में सहयोग करना चाहिए तथा बहुपक्षीय AI जोखिम प्रबंधन ढांचे की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिखाई

2026–27 में भारत की औसत उपभोक्ता महंगाई 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। ADB ने अपना अनुमान 5 प्रतिशत रखा है। दोनों संस्थाओं ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों, भू–राजनीतिक तनाव और मौसम संबंधी जोखिमों का अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कारक माना है। महंगाई का वास्तविक असर आंकड़ों से ज्यादा परिवार के मासिक बजट में दिखाई देता है। भोजन, किराया, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे खर्चों में वृद्धि होने पर नाममात्र आय बढ़ने के बावजूद वास्तविक क्रयशक्ति पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए आर्थिक नीति की सफलता का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह होना चाहिए कि आम परिवार की आय और खर्च के बीच संतुलन कितना सुधरता है। छोटे कारोबारों के लिए विकास का अर्थ आने वाले समय में नीति का ध्यान तीन स्तरों पर समान रूप से होना चाहिएकृउत्पादन और निवेश बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करना और महंगाई को इस स्तर पर रखना कि परिवारों की वास्तविक क्रयशक्ति कमजोर न पड़े।

संपादकीय

महंगा कच्चा तेल:वैश्विक तनाव का भारत की रसोई और परिवहन पर असर

कंपनियों की लाभप्रदता और नकदी स्थिति प्रभावित हो सकती है तथा उनकी अल्पकालिक उधारी की जरूरत बढ़ सकती है। दूसरी ओर, यदि बढ़ी हुई लागत पूरी तरह उपभोक्ता पर डाल दी जाए तो परिवहन और अर्थव्यवस्था के लगभग हर हिस्से तक पहुंच सकता है। ट्रक और मालवाहक वाहन महंगे ईंधन पर चलते हैं तो परिवहन लागत बढ़ती है। परिवहन लागत बढ़ने पर खाद्यान्न, सब्जियां, दूध, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा के दूसरे सामान की कीमतों पर दबाव बन सकता है। विमानन ईंधन महंगा होने पर हवाई यात्रा और माल ढुलाई की लागत प्रभावित हो सकती है। यानी तेल केवल वाहन चलाने का साधन नहीं है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था के उत्पादन और वितरण तंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमत में अचानक और लंबे समय तक बनी रहने वाली तेजी महंगाई के मोर्चे पर भी चुनौती बन सकती है। सरकार और तेल कंपनियों के सामने कठिन संतुलन मौजूदा स्थिति में नीति–निर्माताओं के सामने दोहरे दबाव काईटिंग मार्जिन का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा है, दूसरी तरफ घरेलू ईंधन कीमतों को अचानक बढ़ाने का असर आम उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यदि तेल कंपनियां लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय लागत से कम कीमत पर ईंधन बेचती हैं तो उनके मुनाफे और नकदी प्रवाह पर दबाव बढ़ सकता है। ICRA ने भी कहा है कि ऊंची कच्चे तेल कीमतों और घरेलू खुदरा कीमतों में स्थिरता से तेल विपणन

पैदा कर सकता है। नीति–निर्माताओं के सामने संतुलन की यही कठिन चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक ढांचे की जरूरत क्यों बताई? गुटेरेस ने महासभा में AI को चार प्रमुख वैश्विक शक्ति–परीक्षाओं में शामिल किया। उनके अनुसार AI मानवता के सामने मौजूद समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, लेकिन यदि उसका शासन कमजोर रहा तो निर्यात, कोडिंग, शोध, ग्राहक सेवा और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इससे उत्पादकता और नवाचार के नए अवसर खोल दिए हैं। लेकिन साथ ही रोजगार के स्वरूप में बदलाव और कुछ कामों के स्वचालन को लेकर चिंता भी बढ़ी है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि AI को विकसित करने वाले देशों को सुरक्षा जोखिमों की जानकारी साझा करनी चाहिए, परीक्षण और मूल्यांकन में सहयोग करना चाहिए तथा बहुपक्षीय AI जोखिम प्रबंधन ढांचे की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिखाई

दी। इस गोलीबारी में उसकी पत्नी बबीता सिंह तथा पूजा कराने आए महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा की मौत हो गई। घटना के समय मौजूद अन्य पुजारियों के वहां से निकल जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि परिवार ने अरविंद

झटकों के प्रति अधिक सक्षम बनाना होना चाहिए। घरेलू उत्पादन पर भी ध्यान जरूरी

भारत में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन आयात पर पूरी निर्भरता समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उत्पादन बढ़ने से आयात जोखिम कुछ हद तक कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना ‘समुद्र मंथन’ को मंजूरी दी, जिसके लिए 2030–31 तक 84,084 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है। सरकार ने इसे घरेलू हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। घरेलू उत्पादन बढ़ाना उपयोगी है, लेकिन इसे पर्यावरणीय मानकों, आर्थिक व्यवहार्यता और दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण के साथ संतुलित करना होगा। तेल संकट और रुपये की चुनौती महंगा तेल केवल ईंधन बाजार को प्रभावित नहीं करता। भारत को कच्चे तेल के आयात के लिए बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च करना पड़ता है। इसलिए लंबे समय तक ऊंची तेल कीमतें रुपये पर भी दबाव डाल सकती हैं। हाल के दिनों में वैश्विक तेल कीमतों और रुपये के चाल के बीच संबंध बाजार में दिखाई दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 22 सितंबर को रुपये की गतिविधियों पर तेल कीमतों और भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप की संभावनाओं का प्रभाव रहा। यदि तेल महंगा रहता है और रुपया कमजोर होता है तो आयातित तेल की रुपये में लागत और बढ़ सकती है। इससे महंगाई तथा चालू खाते पर दबाव का जोखिम बढ़ता है। आम परिवार के लिए असली चिंता

आर्थिक नीति की भाषा में तेल कीमतों को डॉलर प्रति बैरल, आयात बिल और राजस्व के आंकड़ों में मापा जाता है। लेकिन आम परिवार के लिए इसका अर्थ कुछ और है। उसके लिए सवाल हैकूमहीने का पेट्रोल–डीजल खर्च कितना बढ़ेगा? गैस सिलेंडर की कीमत पर कितना असर होगा? स्कूल बस, ऑटो, टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन का खर्च कितना बढ़लेगा? बाजार से आने वाला सामान कितना महंगा होगा? इसलिए ऊर्जा नीति को उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखना भी जरूरी है। विशेष रूप से निम्न आय वर्ग और छोटे कारोबारियों को तेल कीमतों के झटके से बचाने के लिए लक्षित उपायों पर विचार किया जा सकता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि किसी भी राहत की व्यवस्था लंबे समय में सरकारी वित्त पर अस्थिर बोझ न बने। संपादकीय दृष्टिकोण

आज की परिस्थिति भारत के सामने एक पुराना लेकिन महत्वपूर्ण सवाल फिर रख रही है क्या हमारी ऊर्जा सुरक्षा केवल पर्याप्त तेल खरीद लेने से सुनिश्चित हो सकती है? जवाब स्पष्ट रूप से व्यापक नीति में छिपा है। रणनीतिक भंडार जरूरी हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। घरेलू उत्पादन जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा जरूरी हैं, लेकिन इनके लिए मजबूत बुनियादी ढांचा भी उतना ही जरूरी है। भारत को ऐसी ऊर्जा नीति की आवश्यकता है जिसमें तात्कालिक मूल्य स्थिरता और दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता दोनों को साथ लेकर

भविष्य केवल तकनीकी रूप से सक्षम देशों और बड़ी कंपनियों द्वारा तय किया जाएगा, तो डिजिटल असमानता का नया दौर पैदा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सामाजिक प्रश्न है। AI के विस्तार का सबसे सीधा प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। कुछ नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, कुछ नौकरियों की प्रकृति बदल सकती है और कई नए पेशे भी पैदा हो सकते हैं। इस बदलाव को केवल नौकरी जाने के सवाल से देखना पर्याप्त नहीं होगा। सरकारों, उद्योगों और शिक्षा संस्थानों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कामगारों को नए कौशल सीखने का अवसर मिले। स्कूल और विश्वविद्यालय भी केवल पारंपरिक पाठ्यक्रमों पर निर्भर नहीं रह सकते। AI साक्षरता, डिजिटल सुरक्षा, डेटा समझ और आलोचनात्मक सोच आने वाले समय की महत्वपूर्ण क्षमताएं होंगी। डेटा और निजता की सुरक्षा AI की ताकत का बड़ा आधार डेटा

आजमगढ़ में पूजा के दौरान गोलीकांड: पत्नी और दो पुजारियों की हत्या

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

संवाददाता अशोक कुमार सिंह

आजमगढ़, 23 सितंबर 2026।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंगलवा थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में मंगलवार शाम धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार, अरविंद सिंह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी बच्चों के साथ घर के एक कमरे में बंद हो गया। करीब सात से आठ घंटे तक चले पुलिस अभियान के दौरान आरोपी के एक बेटे की भी गोली लगने से मौत हो गई। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल अरविंद सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। पहचान पत्र मांगने को लेकर विवाद की बात प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार, मंगलवार शाम करीब छह बजे अरविंद सिंह घर लौटा, जहां धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। वहां मौजूद पुजारियों से पहचान पत्र, विशेष रूप से आधार कार्ड, दिखाने को लेकर पूछताछ के बाद विवाद बढ़ा। पुलिस के मुताबिक, कहासुनी के बाद अरविंद ने अपने लाइसेंसी हथियार से गोलीबारी कर

अधिकारी और कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मकान को घेर लिया और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आरोपी से बातचीत कर आत्मसमर्पण कराने का प्रयास किया। करीब सात घंटे तक पुलिस और आरोपी के बीच गतिरोध बना रहा। पुलिस अधिकारियों की ओर से उसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने और हथियार छोड़ने के लिए समझाने का प्रयास किया गया। बेटे की गोली लगने से मौत पुलिस के अनुसार, गतिरोध के दौरान कमरे के भीतर से गोली चलने की आवाज आई। पुलिस टीम ने अंदर जाकर देखा तो आरोपी अपने बच्चों के साथ घर के एक कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस

दी। इस गोलीबारी में उसकी पत्नी बबीता सिंह तथा पूजा कराने आए महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा की मौत हो गई। घटना के समय मौजूद अन्य पुजारियों के वहां से निकल जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि परिवार ने अरविंद



उसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने और हथियार छोड़ने के लिए समझाने का प्रयास किया गया। बेटे की गोली लगने से मौत पुलिस के अनुसार, गतिरोध के दौरान कमरे के भीतर से गोली चलने की आवाज आई। पुलिस टीम ने अंदर जाकर देखा तो आरोपी अपने बच्चों के साथ घर के एक कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस

मंड्या में जल जीवन मिशन की रफ्तार पर सवाल, लंबित कामों के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे विधायक



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु /मंड्या, 23 सितंबर 2026। मंड्या जिले में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति, फंड की कमी और योजनाओं के अनुमानित खर्च में अंतर को लेकर बुधवार को विकास सौधा में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले के विधायकों ने कई क्षेत्रों में काम अधूरे रहने, ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने और कुछ स्थानों पर पाइपलाइन व सड़क संबंधी कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। बैठक में जल संसाधन मंत्री एन. चलुवरायस्वामी ने कहा कि लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए मंड्या जिले के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनके साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करे और राज्य सरकार से आवश्यक अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करे। मंत्री ने कहा कि योजना के प्रारंभिक अनुमान और बाद में किए गए कार्यों में अंतर बढ़ने के कारण वित्तीय जरूरत भी बढ़ी है। उनके अनुसार, निर्धारित कार्यों के अलावा स्थानीय मांग के आधार पर अतिरिक्त काम शुरू किए जाने से

को दिसंबर 2028 तक पूरा करने की दिशा में तेजी लाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने सुझाव दिया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों को आवश्यक धनराशि के साथ वित्त विभाग के समक्ष रखा जाए। वहीं, जिन ठेकेदारों ने जलधारे परियोजना के तहत स्वीकृत कार्य अभी तक शुरू नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस जारी कर कार्य प्रारंभ करने और गति बढ़ाने के निर्देश देने की बात कही गई। विधायकों ने काम की गुणवत्ता पर उठाए सवाल बैठक में मंड्या जिले के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों से जुड़ी समस्याएं सामने रखीं। विधायकों ने दावा किया कि कई स्थानों पर काम अधूरा है और ठेकेदारों को भुगतान लंबित है। उन्होंने कुछ सड़कों की खुदाई के बाद उनकी मरम्मत ठीक तरीके से नहीं किए जाने तथा अलग-अलग स्थानों पर काम की गति में असमानता का मुद्दा उठाया। कुछ विधायकों ने पहले चरण में हुए पाइपलाइन कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर पाइप पर्याप्त गहराई में नहीं बिछाए गए। इन शिकायतों की स्वतंत्र तकनीकी जांच अथवा गुणवत्ता वित्त विभाग से इस विषय पर चेक करेंगे। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि मार्च तक आवश्यक राशि का एक हिस्सा और उसके बाद शेष राशि जारी करने की योजना पर वित्त विभाग के साथ चर्चा की जाए, ताकि कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। एक वर्ष में सिंगल विलेज, दिसंबर 2028 तक मल्टी विलेज योजना समीक्षा के दौरान सिंगल विलेज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखने तथा मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के कार्यों

वित्तीय संकट को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, आर. अशोक ने मांगा सीएम का इस्तीफा

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 23 सितंबर 2026। कर्नाटक में सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को विधान सभा परिसर में केंगल हनुमंतैया की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार पर वित्तीय प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी सहित पार्टी के विधायक एवं विधान परिषद सदस्य मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने राज्य के वित्तीय हालात को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। वित्त विभाग की टिप्पणी को बनाया आधार आर. अशोक ने अपने संबोधन में वित्त विभाग की हालिया टिप्पणी का हवाला देते हुए सरकार पर बड़े पैमाने पर वित्तीय घोषणाएं करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब राज्य की उधार लेने की क्षमता सीमित हो चुकी है, तब नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणाओं पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वित्त विभाग ने 17 सितंबर की अपनी

टीप्पणी में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के महेंजर नए बड़े खर्च वाले प्रोजेक्ट शुरू करने में सावधानी बरतने की बात कही थी। विभाग ने मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धताओं और लंबित कार्यों के बोझ को देखते हुए यथाव्यवधि एवं विवेकपूर्ण वित्तीय योजना पर जोर दिया है। दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के लंबित कार्यों का मुद्दा भाजपा ने राज्य में लंबित कार्यों और बकाया भुगतानों का मुद्दा भी उठाया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वित्त विभाग की टिप्पणी में विभिन्न विभागों में लंबित कार्यों की लागत दो लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का उल्लेख किया गया है। वहीं लोक निर्माण, जल संस्कार के लघु सिंचाई तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभागों में लंबित बिलों का आंकड़ा करीब 36,136 करोड़ रुपये बताया गया है। आर. अशोक ने आरोप लगाया कि सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई है कि किसानों, पेशनधारियों, शिक्षकों, परिवहन क्षेत्र और अन्य वर्गों से जुड़े भुगतान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार की विभिन्न घोषणाओं और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बीच तालमेल पर भी सवाल उठाए। सरकार पर घोषणाओं को लेकर निशाना आर. अशोक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और सरकार के स्तर पर अलग-अलग क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणाएं



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 23 सितंबर 2026। सिल्क बोर्ड जंक्शन पर रोजाना आने-जाने वाले हजारों यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु साउथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पलाईओवर के निचले हिस्से के व्यवस्थित विकास की योजना पर काम शुरू किया है। साउथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के. एन. रमेश ने बुधवार को होसुर रोड के अंतिम छोर पर स्थित सिल्क बोर्ड पलाईओवर के नीचे के हिस्से का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं

विकसित करने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि पलाईओवर के नीचे के क्षेत्र को इस तरह विकसित किया जाए कि पैदल यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता मिल सके। इसके लिए बैठने की व्यवस्था, उचित प्रकाश व्यवस्था, साफ—सफाई और व्यवस्थित पैदल मार्ग विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। यात्रियों के लिए बैठने और विश्राम की सुविधा सिल्क बोर्ड बेंगलुरु के प्रमुख यातायात जंक्शनों में शामिल हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री बसों, निजी वाहनों और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों से

NVDA उपयंत्री गिरफ्तार

दौरान रिश्तत की मांग की पुष्टि होने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की योजना बनाई गई। तकनीकी कक्ष में पहली किश्त लेते पकड़े गए बुवार को लोकायुक्त की टीम ने योजना के तहत कार्रवाई की। ठेकेदार 14 हजार रुपये की कथित पहली किश्त लेकर पुनासा स्थित NVDA कार्यालय पहुंचा। लोकायुक्त के मुताबिक, कार्यालय के तकनीकी कक्ष में जैसे ही उपयंत्री अशोक गौतम ने रकम ली, सादे कपड़ों में मौजूद टीम ने उन्हें पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्तत की रकम बरामद की गई। कार्रवाई का नेतृत्व लोकायुक्त निरीक्षक सचिन पटेरिया ने किया। टीम में प्रधान आरक्षक विजय कुमार, प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा तथा आरक्षक कमलेश परिहार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम के तहत मामला लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, आरोपी उपयंत्री अशोक गौतम के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में आगे की वैधानिक जांच और कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त की कार्रवाई के संबंध में उपलब्ध रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि अशोक गौतम ने रकम ली, सादे कपड़ों में मौजूद टीम ने उन्हें पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्तत की रकम बरामद की गई। कार्रवाई का नेतृत्व लोकायुक्त निरीक्षक सचिन पटेरिया ने किया। टीम में प्रधान आरक्षक विजय कुमार, प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा तथा आरक्षक कमलेश परिहार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। भ्रष्टाचार

हुब्बल्ली का 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, दुनिया में सबसे लंबा होने का रिकॉर्ड



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
हुब्बल्ली, 23 सितंबर 2026। कर्नाटक के हुब्बल्ली शहर स्थित श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुब्बल्ली जंक्शन ने भारतीय रेलवे को दुनिया के रेल मानचित्र पर एक खास पहचान दिलाई है। यहां का रेलवे प्लेटफॉर्म 1,507 मीटर लंबा है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में दर्ज किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस रिकॉर्ड का सत्यापन 12 जनवरी 2023 को दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बल्ली मंडल द्वारा किया गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक, प्लेटफॉर्म का निर्माण हुब्बल्ली रेलवे स्टेशन के यार्ड के पुनर्विकास का हिस्सा था। इसका उद्देश्य रेल परिचालन की दक्षता बढ़ाने, ट्रेन संचालन की सुरक्षा बेहतर करने तथा यात्रियों के लिए सुविधाओं और आराम में सुधार करना था। गोरखपुर से आगे निकला हुब्बल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1,507 मीटर की लंबाई के कारण यह

प्लेटफॉर्म रेल यात्रियों और देश—विदेश से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट में भी हुब्बल्ली में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को समर्पित किए जाने का उल्लेख मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार, 12 मार्च 2023 को हुब्बल्ली—धारवाड़ क्षेत्र से जुड़े रेलवे विकास कार्यों के साथ विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को समर्पित किया गया था। 14 फुटबॉल मैदानों से भी लंबा प्लेटफॉर्म की 1,507 मीटर लंबाई को आम फुटबॉल मैदान की लगभग 105 मीटर लंबाई से तुलना करें तो यह करीब 14.4 फुटबॉल मैदानों के बराबर बेढती है। इसलिए यह कहना अधिक सटीक होगा कि इसकी लंबाई यार्ड के पुनर्विकास का हिस्सा था। हालांकि फुटबॉल मैदानों के वास्तविक आकार में अंतर हो सकता है, इसलिए इसे एक तुलनात्मक उदाहरण के रूप में देखना चाहिए, न कि प्लेटफॉर्म पर वास्तविक मैदानों के समा जाने के दावे के रूप में। इतना लंबा प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया? हुब्बल्ली दक्षिण पश्चिम रेलवे के महत्वपूर्ण रेल केंद्रों में शामिल है। यहां रेल परिचालन की बढ़ती जरूरतों और यार्ड के पुनर्विकास को ध्यान में रखते हुए

सिल्क बोर्ड पलाईओवर के नीचे बनेगा सुविधाजनक पैदल क्षेत्र, विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश

आवागमन करते हैं। ऐसे में बस या अन्य वाहन का इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए बैठने और कुछ समय आराम करने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। कमिश्नर ने निगम के इंजीनियरों को पूरे क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा। इसमें यात्रियों की आवाजाही, बैठने की जगह और पैदल मार्ग को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के उपयोग का समग्र खाका तैयार किया जाएगा। बेलंदूर मॉडल से विकास की प्रेरणा अधिकारियों के अनुसार बेलंदूर पलाईओवर के निचले हिस्से को नगरपालिका और वकालूर NGO के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसे स्थानीय लोगों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसी मॉडल की तर्ज पर सिल्क बोर्ड पलाईओवर के नीचे के हिस्से को भी बेहतर बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। वकालूर NGO के प्रमुख अरुण पई ने निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त से क्षेत्र में आवश्यक अन्य विकास कार्य कहां का अनुरोध किया। संगठन की ओर से इस सप्ताहत पलाईओवर के पिलरों को आकर्षक रूप देने के लिए पेंटिंग

का कार्य किए जाने की जानकारी भी दी गई। सफाई, फुटपथ और नालियों पर भी जोर निरीक्षण के दौरान पलाईओवर के नीचे और आसपास के फुटपथ की सफाई तथा क्षेत्र को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। स्थानीय स्तर पर क्षेत्र में जमा कचरे और गंदगी को हटाने, जमीन को समतल करने तथा पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए खुले नालों को स्लैब से ढकने की जरूरत बताई गई। कमिश्नर ने क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि रात के समय पैदल यात्रियों के साथ—साथ वाहन चालकों को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। मेट्रो स्टेशन से BMTC बस स्टैंड तक बेहतर फुटपथ सिल्क बोर्ड मेट्रो स्टेशन से BMTC बस स्टैंड तक पैदल आने—जाने वाले यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने को निर्देश दिया गया कि इस मार्ग आवश्यक अन्य विकास कार्य कहां का अनुरोध किया। संगठन की ओर से इस सप्ताहत पलाईओवर के पिलरों को आकर्षक रूप देने के लिए पेंटिंग

सर्व पितृ मोक्ष के लिए 108 कुंडीय महायज्ञ और श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

आचार्य प्राणनाथ जी महाराज ने बताया कि उनके 40 दिवसीय उपवास का समापन वरिष्ठ समाजसेवी डॉ. पहल



सिंह सैनी एवं खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। संगठन की ओर से बताया गया कि धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सहभागिता को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। पदाधिकारियों ने की सहभागिता

प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, प्लेटफॉर्म का निर्माण के हिस्से के शीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसका प्रमुख उद्देश्य परिचालन क्षमता, ट्रेन संचालन की सुरक्षा तथा यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लंबे प्लेटफॉर्म के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों और अधिक कोच वाली ट्रेनों के परिचालन में भी प्लेटफॉर्म क्षमता के बेहतर उपयोग संभव होता है। यह विशेषता बड़े रेल जंक्शन के रूप में हुब्बल्ली की भूमिका को भी रेखांकित करती है। संत सिद्धारूढ़ स्वामीजी के नाम पर स्टेशन हुब्बल्ली जंक्शन का आधिकारिक नाम श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुब्बल्ली जंक्शन है। इसका नाम मार्च 2023 को हुब्बल्ली—धारवाड़ क्षेत्र से जुड़े रेलवे विकास कार्यों के साथ श्रामीजी के सम्मान में रखा गया है। यह स्टेशन कर्नाटक के प्रमुख रेल केंद्रों में से एक है और दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बल्ली मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों में शामिल है। लंबे प्लेटफॉर्म का विश्व रिकॉर्ड इस स्टेशन की पहचान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ता है। गिनीज रिकॉर्ड से मिली वैश्विक पहचान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज 1,507 मीटर का यह रिकॉर्ड केवल हुब्बल्ली ही नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। रिकॉर्ड के आधिकारिक विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह उपलब्धि दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बल्ली मंडल ने हुब्बल्ली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में हासिल की। इस तरह कर्नाटक का हुब्बल्ली जंक्शन अपनी रेल सेवाओं के साथ—साथ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के कारण भी विशेष पहचान रखता है।